10/03/2026

आकाशवाणी ईटानगर

उप-मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज विधानसभा में वित्त वर्ष दो हजार छब्बीस - सत्ताईस के लिए अरुणाचल प्रदेश का बजट पेश किया। इस वित्त वर्ष के लिए बजट अनुमान छत्तीस हजार छह सौ सात करोड़ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में आठ दशमलव एक प्रतिशत कम है। श्री मेन ने कहा कि "यह बजट राज्य की प्रगति के लिए एक व्यापक रूपरेखा तैयार करता है, जिसमें एक मज़बूत और अधिक समृद्ध राज्य के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, जन-केंद्रित नीतियों, आर्थिक विकास, उद्यमिता, ज़िम्मेदार राजकोषीय प्रबंधन और शासन सुधारों पर विशेष ज़ोर दिया गया है।"

0000000000000000000000

राज्य के बजट 2025-26 में, उपमुख्यमंत्री चाउना मेन ने स्वास्थ्य और चिकित्सा क्षेत्र में कई परियोजनाओं की घोषणा की। ट्रीम्स में नए ऑपरेशन थिएटर, जिनमें कार्डियो-वैस्कुलर OT आदि भी बनाने की घोषणा की गई। तातो में एक नया ज़िला अस्पताल और नाफरा में एक नया अस्पताल बनाने की योजना पर भी काम चल रहा है। सभी ज़िलों में चरणबद्ध तरीके से आपातकालीन और ट्रॉमा केंद्र बनाए जाएँगे। डिजिटल स्वास्थ्य पहल को मज़बूत करते हुए, सरकार मरीज़-केंद्रित देखभाल के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखेगी। रीनल केयर, कैंसर थेरेपी और मुख्यमंत्री अंग प्रत्यारोपण योजनाओं के तहत मिलने वाली सहायता को बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही, अरुणाचल प्रदेश नशा निवारण मिशन भी शुरू किया गया।

0000000000000000000000

राज्य के लोगों के लिए शिक्षा के क्षेत्र में खुश होने के कई मौके थे। बुनियादी शिक्षा को मज़बूत करने के लिए एक व्यापक 'राज्य प्रारंभिक बाल देखभाल और शिक्षा नीति' शुरू की गई। स्थानीय भाषाओं को बचाने और बढ़ावा देने पर खास ध्यान दिया जाएगा। इसके लिए, कक्षा 1 से 8 तक के लिए 'तीसरी भाषा नीति' लागू की गई। हायर सेकेंडरी स्कूलों और कॉलेजों में चरणबद्ध तरीके से एनिमेशन, ऑडियो और विज़ुअल लैब बनाई जाएंगी। एक ऐतिहासिक कदम के तहत, पासीघाट में अरुणाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में 'जापानी भाषा अध्ययन केंद्र' स्थापित किया जाएगा।

00000000000000000000

कृषि क्षेत्र में भी कई परियोजनाओं और पहलों की घोषणा की गई। शहद उत्पादन इकाइयों की स्थापना, 'कीवी मिशन' और 'मशरूम विकास मिशन' के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत सरकार के सहयोग से दिरांग स्थित 'याक फाइबर प्रोसेसिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर' में मिथुन और याक पालन को बढ़ावा दिया जाएगा।

0000000000000000

अरुणाचल प्रदेश की 8वीं विधानसभा ने आज अपने बजट सत्र में, इस साल 20 फरवरी को दिल्ली के मालवीय नगर में पूर्वोत्तर की तीन महिलाओं के साथ हुए नस्लीय भेदभाव की कड़ी निंदा की। कई विधायकों और पर्यटन मंत्री श्री पी.डी. सोना ने एक साथ मिलकर इस घटना को चौंकाने वाला, असहनीय, अपमानजनक, बेहद दुखद और अनादरपूर्ण बताया।

सदन ने देश को पूर्वोत्तर के लोगों के उन योगदानों की याद दिलाई, जो उन्होंने सीमाओं की रक्षा करने, और खेल, शिक्षा तथा अन्य क्षेत्रों में देश का गौरव बढ़ाने में दिए हैं। यह कहते हुए कि विधानसभा राज्य के बाहर पढ़ाई कर रहे छात्रों के साथ पूरी तरह से खड़ी है, सदन ने सभी पूर्वोत्तर राज्यों को एकजुट करके PMO और गृह मंत्रालय से एक 'नस्ल-विरोधी कानून' लाने का अनुरोध करने का भी संकल्प लिया; ताकि दोषियों को कड़ी सज़ा दी जा सके और भविष्य में भेदभाव की ऐसी घटनाओं को पूरी तरह से खत्म किया जा सके।

0000000000000000000000

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में ‘रक्षा बल विज़न दो हजार सैतालीस: भविष्य के लिए तैयार भारतीय सेना का एक रोडमैप’ जारी किया। यह विज़न दस्तावेज़ रक्षा बलों के भीतर आवश्यक रणनीतिक सुधारों, क्षमताओं में वृद्धि और संगठनात्मक परिवर्तनों की रूपरेखा प्रस्तुत करता है, ताकि बदलते भू-रणनीतिक, तकनीकी और सुरक्षा परिवेश का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। यह सेना को एक एकीकृत, बहु-क्षेत्रीय और चुस्त बल में बदलने की परिकल्पना करता है, जो तेज़ी से बदलते वैश्विक और क्षेत्रीय घटनाक्रमों के बीच, विरोधियों को रोकने, संघर्ष के पूरे दायरे में प्रतिक्रिया देने और बढ़ते रणनीतिक हितों की रक्षा करने में सक्षम हो।

0000000000000000000000

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) ने सामाजिक विज्ञान की एक पाठ्यपुस्तक 'एक्सप्लोरिंग सोसाइटी: इंडिया एंड बियॉन्ड, ग्रेड 8 (भाग-II)' को वापस ले लिया है, जिसमें 'हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका' (The Role of Judiciary in our Society) शीर्षक वाला चौथा अध्याय शामिल था। NCERT ने बताया कि पूरी किताब वापस ले ली गई है और अब उपलब्ध नहीं है। NCERT के निदेशक और सदस्यों ने उक्त चौथे अध्याय के लिए बिना किसी शर्त के माफी मांगी है।

0000000000000000000000

ज़िला परिषद की अध्यक्षा बामांग यायु ने कल, ज़िला परिषद कार्यालय, यूपिया के कॉन्फ्रेंस हॉल में सभी विभागों के प्रमुखों और ज़िला परिषद सदस्यों के साथ एक समन्वय बैठक बुलाई। इस बैठक में, ZPC यायु ने सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों और निर्वाचित PRI सदस्यों के बीच घनिष्ठ समन्वय की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। ZPC यायु ने इस बात पर ज़ोर दिया कि ऐसे प्रस्ताव ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत अध्यक्षों के माध्यम से शुरू होने चाहिए, फिर ZPMs तक पहुँचने चाहिए और अंत में विचार-विमर्श के लिए ज़िला स्तर तक पहुँचने चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि वे नव-निर्वाचित ZPMs को विभागीय नीतियों और चल रही योजनाओं के बारे में मार्गदर्शन दें, ताकि वे लोगों की बेहतर सेवा कर सकें।

0000000000000000000000